be disbursed through North East Development Financial Corporation.

4. Growth Centres & IIDCs become total tax-free zones (income tax and excise) for 10 years and 15% subsidy on Plant & Machinery subject to a ceiling of Rs. 30 lakhs.

5. Comprehensive Insurance Scheme for new industrial units.

(b) to (d) The details of the New Industrial Policy for the North East have been announced by the Government on December 24, 1997. Steps have already been taken to operationalise the policy guidelines and necessary notifications have also been issued. However, in respect of certain issues where decsion has to be taken in consultation with various States Governments and/other Departments, necessary notifications would be issued shortly.

(e) While planning and development of industries within a state is primarily the responsibility of the concerned State Government, the Central Government has been supplementing the efforts of the North East State Governments for rapid industrialisation through special central assistance under special area programme of the North East Council and through recently announced New Industrial Policy for the North East region.

एन0 आई0 डी0 सी0 की स्ट्रैटजिक सेल

2173. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि विनिवेश/संयुक्त उद्यम के रूप में एन0 आई0 डी0 सी0 की 'स्ट्रैटजिक सेल' पर विचार किया जा रहा हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सरकार ने वित्तीय एवं तकनीकी योगदान मुहैया कराने में समर्थ सहयोगी को शामिल करके एन0 आई0 डी0 सी0 को सिद्धांत रूप से संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित करने का निर्णय से लिया हैं। यह निर्णय कंपनी को मजबूत बनाने की दृष्टि से लिया गया हैं । इस उद्देश्य के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई हैं ।

Amendment of Patents Act

2174. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have approached the World Trade Organisation (WTO) to appoint an arbitrator to gain sometime to amend its Patents Act of 1970;

(b) if so, the reasons therefor and the reaction of the W.T.O. thereto; and

(c) the specific areas where the aforesaid Patents Act is sought to be amended?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No final decisions have yet been taken by the Government regarding amendment to the patents Act, 1970.

Proposals for Industries in NE States

2175. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

. (a) whether the proposal of industries/ items for automatic approval for foreign equity upto 74%, from the North Eastern States have been submitted;

(b) if so, what are the proposals of each State; and

(c) what is the time for approval and by when it will be started?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) No, Sir. Foreign Collaboration proposals that satisfy the parameters prescribed for automatic approval come under the purview of the Reserve JBank of India (RBI). As per the latest guidelines, no further approval is required from RBI except I that the Companies entering into such

collaborations are required to file the requisite, documents with the RBI within days after issue of shares to the foreign investors.

औद्योगिक विकास दर

2176. **श्री अखिलेश दास :**
श्री रहसबिहारी बारिक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की औद्योगिक विकास दर कितनी दर्ज की गई,

(ख) घरेलू स्तर पर यह विकास दर कितनी थी,

(ग) क्या विकास दर में वृद्धि या कमी पाई गई हैं,

(घ) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 की तुलना में यह विकास दर कितनी हैं और क्या इसमें कोई गिरावट आई हैं,

(ड़) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) क्या राज्यों का विकास दर में अत्यधिक असमानता हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ड़) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार अभिवृद्धि दर (आधार 1993-94=100) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए क्रमशः 12.7, 5.6 और 6.6 प्रतिशत थी। अभिवृद्धि दर 1996-97 में घट गई थी जो 1997-98 में बढ़ गई।

(च) राज्यों की अभिवृद्धि दरें तुलनात्मक नहीं हैं क्योंकि सूचकांक जारी करने संबंधी आधार वर्ष, अवधि प्रयुक्त डाटा स्त्रोत आदि की पसंद में अन्तर होता हैं।

कुछ राज्यों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना की असफलता

2177. **श्री चीमनभाई हरी भाई शुक्ला :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि बैंको, के असहयोग और अप्रभावी कार्यकरण के कारण उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात के नगरपालिका क्षेत्रों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना पूर्णतया असफल रही हैं,

(ख) क्या इन राज्यों के कुछ हिस्सों में इन योजनाओं का प्रभावी प्रचार नहीं किया गया था,

(ग) क्या इस असफलता में राज्य सरकारें भी उत्तरदायी हैं,

(घ) यदि हां, तो इन सभी कारकों के संबंध में किए गए अध्ययान का ब्यौरा क्या हैं, और

(ड़) वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान विशेष रूप से उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात के शहरों की वास्तविक स्थिति क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) (घ) प्रधान मंत्री रोजगार को उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात के शहरी क्षेत्रों में संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित किया गया हैं। इन राज्यों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, इस योजना को अखबारों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रचारित किया गया था।

अक्तूबर, 1989 से नवंबर, 1997 तक शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा नेहरू रोजगार योजना क्रियान्वित की गयी थी। कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बैंको द्वारा सहयोग प्रदान न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने अपने वास्तविक लक्ष्यों को पार किया है, जबकि गुजरात में उपलब्धियां लक्ष्य सें कम रही।

"शहरी और पर्यावरण संबंधी क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र' द्वारा गुजरात के कुछ चुनिंदा कस्बों में नेहरू रोजगार योजना के क्रियान्वयन पर किये गये अध्ययन में मसौदे पर आधारित निष्कर्षों का विवरण विवरण-I में दिया गया हैं। (नीचे देखिए)

(ड़) प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे 02.10.1993 से क्रियान्वित किया जा रहा हैं, 1993-94 के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित की गयी थी। 1994-95 से इस योजना को देश के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा हैं। राज्यों द्वारा यह सूचित किया गया हैं कि 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रधानतंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शानें वाला विवरण विवरण-II पर हैं। (नीचे देखिए)

उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान, नेहरू रोजगार योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शानें वाला विवरण विवरण-III पर हैं।